



[उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से कौशल विकास और क्षमता निर्माण में भूमिका का अध्ययन]

आदित्य नारायण

शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा.

ईमेल आईडी: anarayanbhu@gmail.com

डॉ. राजेश सिंह चौहान, सहायक प्रोफेसर

नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोगांव, मैनपुरी.

ईमेल आईडी: drrajeshsinghchauhanndc@gmail.com

ABSTRACT

उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय संसाधनों, पारम्परिक कौशल एवं क्षेत्रीय विशिष्टताओं के समन्वय के द्वारा समावेशी आर्थिक विकास का एक प्रभावशाली मॉडल को अपनाया गया है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 को किया गया था। इस शोध पत्र में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कारीगरों, बुनकरों, हस्तशिल्पकारों एवं महिलाओं और युवाओं को उन्नत तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना, नई डिजाइन का निर्माण करना और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण करने पर केंद्रित किया गया। इस योजना के माध्यम से न केवल छोटे एवं स्थानीय उद्योगों के पुर्नजीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बल्कि छोटे – छोटे स्तर पर रोजगार उत्पन्न करना, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करना और उन लोगों को कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान दिया जा रहा है जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान किया जा सके। इस योजना के सामने डिजिटल अवसंचना का अभाव, जानकारी का अभाव, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कमी आदि जैसी चुनौतियाँ उभर कर आ रही है। उपर्युक्त समस्या का निदान सही तरीके से किया जाए तो यह योजना उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर, संतुलित विकास और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के साथ ही कारीगरों में कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण को मजबूती प्रदान करना एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस शोध पत्र में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए द्वितीयक स्रोतों जैसे प्रकाशित शोध पत्रों, किताबों, एक जिला एक उत्पाद योजना से संबंधित रिपोर्ट, एमएसएमई की रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण और विभिन्न वेबसाइट का प्रयोग किया गया।

KEYWORDS: उत्तर प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद योजना, कौशल विकास, क्षमता निर्माण ।

Received	Accepted	Published	Article Type
25/06/2026	05/08/2026	14/08/2026	Research Paper



प्रस्तावना : उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय संसाधनों, पारम्परिक कौशल एवं क्षेत्रीय विशिष्टताओं के समन्वय के द्वारा समावेशी आर्थिक विकास का एक प्रभावशाली मॉडल को अपनाया गया है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों से वहाँ के विशिष्ट उत्पादों को चुनाव किया गया है जैसे आगरा का पेटा, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद की धातु के बर्तन, वाराणसी की बनारसी सिल्क साड़ी, भदोही की कालीन, फिरोजाबाद की कांच उत्पाद, अलीगढ़ की ताले एवं हार्डवेयर, अयोध्या की गुड़ उत्पाद, आजमगढ़ की काली मिट्टी के बर्तन, बाराबंकी की हथकरघा उत्पाद, चंदौली की जरी – जरदोजी, गोरखपुर की टेराकोटा उत्पाद, हरदोई की हथकरघा उत्पाद, मैनपुरी की तारकशी कला आदि देश – विदेश में प्रसिद्ध है। परंतु वैश्वीकरण तकनीकी पिछड़ापन बाजार तंत्र की कमजोरी एवं औद्योगीकरण के कारण इन प्रारंभ पर अधिक उद्योगों को समय के साथ अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण कारीगरों और बुनकरों की आय तथा रोजगार के अवसरों में गिरावट देखने को मिल रहा है। इन समस्याओं के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुरुआत किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक जिले के वहाँ विशिष्ट उत्पादों को को प्रोत्साहन करना है। जिससे वहाँ के स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन, वहाँ की युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करना तथा आर्थिक सशक्तिकरण को को प्रोत्साहन प्रदान है। इस योजना के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण एवं विकास पर जोर दिया जा रहा है। उन्हें आधुनिक तकनीक, वित्तीय बाजार, वैश्विक बाजार तथा डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहन किया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना के द्वारा युवाओं, बुनकरों और कारीगरों को प्रशिक्षण, उत्पादन, उद्यमिता विकास तथा बाजारों के आधुनिक संसाधनों के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जिसके के माध्यम से उनकी दक्षता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि किया जा रहा है। इसके अलावा संस्थागत सहयोग और क्लस्टर आधारित विकास के द्वारा उत्पादक संरचना को मजबूत किया जा रहा है और जिससे स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान किया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार “आत्मनिर्भर भारत” की अवधारणा के अनुरूप ही स्थानीय स्तर पर उत्पादन, स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित के साथ ही क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, बुनकरों और कमजोर लोगों को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है। जिससे उन्हें विकास के मुख्य आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज के समय पुरे दुनिया में प्रतिस्पर्धा का दौर जैसे बाजार की पहुँच, नवाचार और गुणवत्तापूर्वक वाली वस्तुओं का उत्पादन चल रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना के द्वारा पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक मांग के अनुसार एक प्रयास प्रभावी किया जा रहा है। इसीलिए इस योजना का अध्ययन न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास और नीति – निर्माण पर रणनीति बनाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है।

इस शोध पत्र के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद योजना की भूमिका का विश्लेषण किया जा रहा है। विशेष रूप से कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण के संदर्भ में ताकि यह समझ जा सके कि इस योजना ने किस प्रकार उत्तर प्रदेश में समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना।
- उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण में आने वाले चुनौतियों का अध्ययन करना।

साहित्यिक समीक्षा

इस शोध पत्र में “उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण में भूमिका का अध्ययन” से संबंधित साहित्य और रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है।

डॉ.राधिका चौधरी और शैली सिंह (2026) के अध्ययन से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के कौशल विकास एवं रोजगार प्रभाव पर आधारित है। इस शोध पत्र में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से क्षेत्रीय कारीगरों एवं उद्यमियों को तकनीक प्रशिक्षण प्रदान करना, आधुनिक उपकरण प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, बाजार सुविधा प्रदान करना, ई – कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुँच प्रदान की



गई है। जिससे पारंपरिक उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि, अनेक लोगों के लिए स्वरोजगार प्रदान तथा नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उद्योगों को संगठित रूप प्रदान करने के साथ – साथ युवाओं में उद्यमिता को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यदि इस योजना को और मजबूती प्रदान करना है तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक बनाया जाए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया सुधार, वित्तीय सहायता, बाजार उपलब्ध के नेटवर्क को मजबूत बनाए जाए योजना का प्रभाव और अधिक व्यापक तथा दीर्घकालीन सकता है। जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगा।

मिस आकांक्षा पटेल (2025) के शोध पत्र से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आर्थिक विश्लेषण पर केंद्रित किया गया है। इस शोध पत्र में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए द्वितीय स्रोतों जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एकेडमिक जनरल, सरकारी रिपोर्ट, शोध पत्रों का प्रयोग किया गया है और गुणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, उत्पादों के गुणवत्ता में सुधार, बाजार उपलब्ध कराना, उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुआ जिससे कारीगरों की आय में सुधार तथा नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हुआ है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे एमएसएमई क्षेत्र को नई गति मिल है। महिलाओं, युवाओं और पारंपरिक शिल्पकारों की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हुआ है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिला है। इस योजना में कुछ चुनौतियां भी आ रही है जैसे बाजार की सीमित पहुंच, वित्तीय संसाधनों की कमी, आधुनिक तकनीक का सीमित उपयोग, डिजिटल की कमी तथा जिलों में जागरूकता का अभाव देखने को मिला है। इन समस्याओं का समाधान किया जाए एवं ई – व्यापार, कौशल विकास, नवाचार और निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए और अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

डॉ. अभिषेक चौधरी और प्रो. राम मिलन (2024) के अध्ययन से पता चलता है कि एक जिला एक उत्पाद व्यवसाय मॉडल पर केंद्रित किया गया है जिसमें विभिन्न देशों में इस मॉडल की सफलता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। एक जिला एक उत्पाद मॉडल के माध्यम उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना, ग्रामीण में विकास करना, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना, युवाओं में कौशल विकास करना एवं निर्यात संवर्धन से स्थानीय स्तर पर असमानताओं को कम करना और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आनंद कुमार शर्मा और पवनेश कुमार (2024) के अध्ययन से बोध होता है कि एक जिला एक उत्पाद योजना मुरादाबाद के धातु शिल्प उद्योग पर केंद्रित किया गया है। जिसमें आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए मुरादाबाद के धातु के क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों और उद्यमियों पर सर्वेक्षण किया गया है तथा द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। इस योजना को कई स्तरों पर मजबूती बनाया गया है तथा सरकार के द्वारा जैसे जिला मेला, निवेशक सम्मेलन, व्यापार प्रदर्शनियों और मेगा क्राफ्ट क्लस्टर स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार तक पहचान मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से उत्पादों की पहचान, बाजार का अवसर, रोजगार में वृद्धि, तथा उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। यदि सरकार ने मुरादाबाद में धातु कारीगरों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास, बाजार और ब्रांडिंग जैसी सुविधा लगातार उपलब्ध कराया जाए से उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगा। इस मॉडल को अन्य राज्यों और देश में भी सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।

डॉ. रश्मि अग्रवाल और डॉ.जावेद आलम (2023) के अध्ययन से पता चलता है की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का 2018–2021 के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करना, योजना के उपलब्धियों की समीक्षा करना और इसके प्रभाव प्रभाव पर केंद्रित किया गया है। इस शोध पत्र में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए द्वितीय स्रोतों जैसे प्रकाशित शोध पत्र, उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट और एक जिला एक उत्पाद पोर्टल का उपयोग किया गया है। इस योजना के द्वारा पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय स्तर के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पहचान मिला, रोजगार, कारीगरों आय, ई – कॉमर्स, सरकारी सहायता, निर्यात तथा एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को मजबूती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परंतु दीर्घकालीन सफलता के लिए ब्रांडिंग, बाजार की उपलब्धता और कौशल विकास लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है।



उमाशंकर यादव और रविंद्र त्रिपाठी (2022) के शोध पत्र के अध्ययन से पता चलता है की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना की भूमिका, वैश्विक हस्तशिल्प और रणनीतियों के विकास पर केंद्रित किया गया है। इस योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना, स्वरोजगार पैदा करना, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना एवं स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है। इस शोध पत्र में ग्लोबल हैंडीक्राफ्ट इंडेक्स विकसित करने का सुझाव दिया गया है जिससे विभिन्न देशों और स्थानीय क्षेत्रों के हस्तशिल्प उत्पादों की गुणवत्ता सुधार करना, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना, निर्यात क्षमता में वृद्धि का मूल्यांकन करना एवं नवाचार पर केंद्रित किया जा सके। इस सूचकांक के माध्यम से भारतीय हस्तशिल्प विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक हो सकता है। यदि इस योजना के माध्यम से सरकार उद्योग, वित्तीय संस्थानों तथा शैक्षणिक संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा सके और डिजिटल बाजार, डिजाइन में सुधार, निर्यात को प्रोत्साहन और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के समावेशी आर्थिक विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्ध में वृद्धि और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

डॉ. गीतिका टंडन कपूर (2020) के शोध पत्र के अध्ययन से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना के प्रदर्शन के मूल्यांकन पर केंद्रित किया गया। यह शोध पत्र वर्णनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। इस शोध पत्र में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार पारंपरिक हस्तशिल्प, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। जिसके अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमों में रोजगार, उत्पादन और आय में वृद्धि देखने को मिल है। इस योजना में कुछ चुनौतियां भी उभर का सामने आ रही है जैसे लोन प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया, तकनीक जानकारी का अभाव, सीमित बाजार सुविधा, नवाचार की कमी और डिजिटल प्लेटफार्म तक पहुंच सीमित। इन समस्याओं को समाधान जैसे लोन प्रक्रिया सरल, बेहतर प्रशिक्षण, कौशल विकास, नवाचार में सुधार, तकनीक सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जाए तो राज्य के समावेशी आर्थिक विकास और स्थानीय उद्यमिता को और तेज गति प्रदान किया जा सकता है।

शोध पद्धति

इस पत्र में वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है और इसमें आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए द्वितीयक स्रोतों जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद संबंधित रिपोर्ट, एमएसएमई की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय कौशल विकास की रिपोर्ट, शोध पत्र, जर्नल और पुस्तकों का प्रयोग किया गया है।

उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से कौशल विकास

कौशल विकास का तात्पर्य है की लोगों के ज्ञान, तकनीक दक्षता में सुधार, कार्य करने की क्षमता में सुधार एवं व्यावसायिक क्षमता का विकास करना होता है। जिसके द्वारा बेहतर वस्तुओं का उत्पादन करना, रोजगार प्राप्त करना और स्वरोजगार स्थापित करने की क्षमता में वृद्धि हो सके।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अनुसार 14 से 35 उम्र के सभी युवाओं को उनके पसंद के ट्रेड में ट्रेनिंग प्रदान करना, अकुशल तथा अर्ध – कुशल वर्कफोर्स के लिए स्किल सीखने एवं अपग्रेड करने की सुविधा प्रदान किया जाता है। जिससे कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, दिव्यांगजनों और अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश में जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका में सामने आ रहा है। जिससे इस योजना के माध्यम से प्रत्येक जिले के पारंपरिक उत्पादों में काम करने वाले कारीगरों शिल्पकारों, बुनकरों, किसानों एवं युवाओं को आधुनिक तकनीक, डिजाइन, गुणवत्ता में सुधार और बाजार संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

जिसको निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है—

पारंपरिक कौशल का संरक्षण प्रदान करना

एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से प्रत्येक जिले के पारंपरिक उत्पादों जैसे वाराणसी का बनारसी सिल्क सिल्क साड़ी, मुरादाबाद का पीतल, फिरोजाबाद का कांच, भदोही का कालीन, आगरा का पेठा, अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का धातुशिल्प, आजमगढ़ का काली मिट्टी के बर्तन, चंदौली की जरी – जरदोजी से जुड़े कारीगरों और बुनकरों को पारंपरिक कौशल को संरक्षित किया जा रहा है। बदलते हुए परिस्थितियों के अनुसार उन्हें आधुनिक उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण देकर उनके कार्य क्षमता में वृद्धि किया जा रहा है।

तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना



एक जिला एक उत्पाद योजना के द्वारा कारीगरों, बुनकरों एवं युवाओं को आधुनिक मशीनों, उपकरणों और नई तकनीक का प्रशिक्षण, पैकेजिंग का प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, मानकीकरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे उत्पादन के गुणवत्ता में सुधार, समय की बचत, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि, निर्यात प्रोत्साहन में वृद्धि तथा कम लागत होती जा रही है। इससे पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक बाजार की मांग के अनुसार बनाया जा रहा है।

उद्यमिता कौशल प्रदान करना

एक जिला एक उत्पाद योजना केवल कौशल तक सीमित नहीं है बल्कि युवाओं बुनकरों, कारीगरों को व्यवसाय प्रबंधन करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, बाजार का सुविधा प्रदान करना, डिजिटल भुगतान जैसी उद्यमिता संबंधित दक्षता का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे स्वरोजगार स्थापित करने तथा अपने उद्योगों का विस्तार करने में सक्षम बनाया जा रहा है।

महिलाओं और युवाओं को सशक्तिकरण प्रदान करना

एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से युवाओं एवं महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिन्हें हथकरघा बुनकरों, हस्तशिल्पकारों और अन्य स्थानीय स्तर पर उद्योगों से जोड़ा जा रहा है तथा जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यमिक क्षमता निर्माण करना

क्षमता निर्माण का तात्पर्य है की संस्थाओं, उद्यमों, समूहों एवं युवाओं में उन क्षमता को विकसित करना होता है। जिसके द्वारा वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से, कुशलता तथा वस्तुओं का उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से संपादित कर सकें।

क्षमता निर्माण में तकनीक का ज्ञान, बाजार क्षमता को विकसित करना, वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना, नवाचार को विकसित करना, प्रबंधकीय कौशल में वृद्धि करना एवं संस्थागत सहयोग को शामिल किया जाता है। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से क्षमता निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे बुनकरों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, कारीगरों और स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन प्रदान करके उनके उत्पादन क्षमता, वस्तुओं के उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता और आय में वृद्धि करता है।

जिसको निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है –

- तकनीकी क्षमता निर्माण करना
- संस्थागत क्षमता निर्माण करना
- वित्तीय और बाजार क्षमता निर्माण करना
- उद्यमिता, नवाचार और निर्यात क्षमता का निर्माण करना

इन्वेस्ट यूपी अचीवमेंट रिपोर्ट 2018– 2024; मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से 2019 से 2023 के दौरान कारीगरों के प्रशिक्षण में वृद्धि हुआ है।

Figure 1: Artisans Trained under ODOP Skill Development Scheme, Uttar Pradesh (2018–2023)

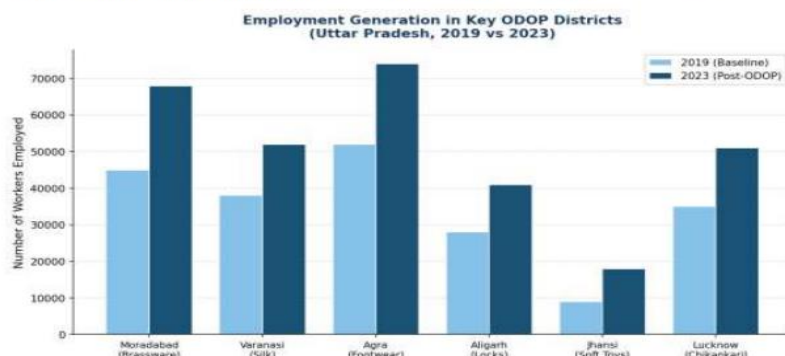


Source: Invest UP Achievement Report 2018–2024; NSDC Annual Reports

इन्वेस्ट यूपी अचीवमेंट रिपोर्ट 2018– 2024; मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से 2019 से 2023 के दौरान मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, झांसी और लखनऊ में रोजगार सृजन में वृद्धि हुआ है। इसको फिगर दो में दिखाया गया है –



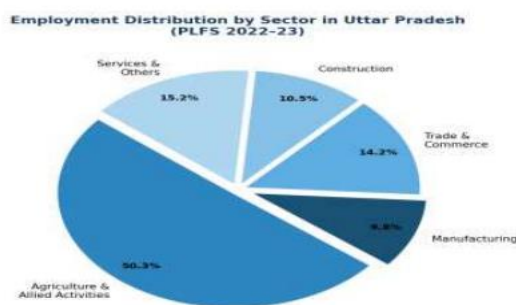
Figure 2: Employment Generation in Key ODOP Districts, Uttar Pradesh (2019 vs 2023)



Source: Invest UP Achievement Report 2018–2024; Government of Uttar Pradesh District Reports

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022–23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार रोजगार वितरण निम्न तरीके से है। सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि और संबंधित क्रियाएं 50.3 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र 15.2 प्रतिशत, ट्रेड और कॉमर्स 14.2 प्रतिशत, कंस्ट्रक्शन 10.5 प्रतिशत और मैन्युफैक्चरिंग 9.6 प्रतिशत है। इसको फिगर तीन में दिखाया गया है –

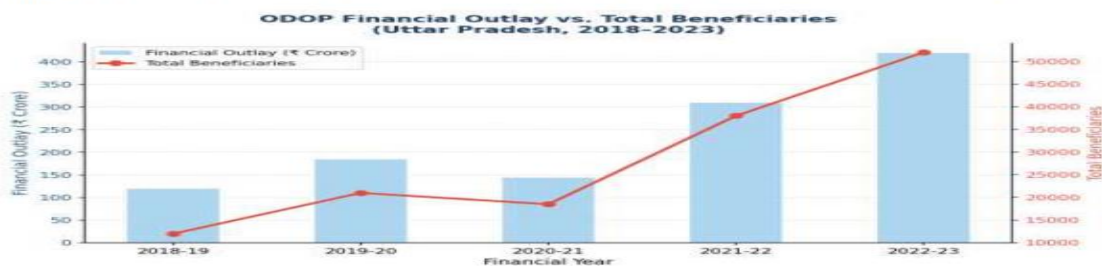
Figure 3: Employment Distribution by Sector in Uttar Pradesh (PLFS 2022–23)



Source: Ministry of Labour and Employment, Periodic Labour Force Survey 2022–23

इन्वेस्ट यूपी अचीवमेंट रिपोर्ट 2018 – 2024; मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना पर वित्तीय व्यय और कुल लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रहा है। इस को फिगर चार में दिखाया गया है –

Figure 4: ODOP Financial Outlay vs. Total Beneficiaries, Uttar Pradesh (2018–2023)



Source: Invest UP Achievement Report 2018–2024; Ministry of MSME Annual Reports



उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के सामने वाली प्रमुख चुनौतियां

उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण में भूमिका का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिला के विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलाने, स्थानीय स्तर पर उद्योग में वृद्धि करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना, स्वरोजगार पैदा करना, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना, युवाओं को आधुनिक मशीनों और उपकरणों का प्रशिक्षण प्रदान करना और बुनकरों एवं कारीगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके बावजूद भी योजना में कुछ चुनौतियां सामने उभर आ रही हैं।

जिसको निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है—

कौशल प्रशिक्षण में कमी

एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रमुख उद्देश्य बुनकरों, कारीगरों, महिलाओं एवं युवाओं को कौशल विकास और क्षमता में वृद्धि करना है। परंतु अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर नियमित प्रशिक्षण संचालित नहीं हो पा रहा है। अनेकों बुनकरों और कारीगरों अभी भी परंपरागत तकनीक पर काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी भी आधुनिक मशीन का ज्ञान का अभाव, डिजाइन बनाने का अभाव, डिजिटल तकनीक और वस्तुओं का उत्पादन के प्रशिक्षण का अभाव है। जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि उसे स्तर तक नहीं हो पा रहे जिस स्तर तक वृद्धि होना चाहिए।

वित्तीय संसाधनों का अभाव

एक जिला एक उत्पाद योजना में बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता जैसे ऋण और सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था किया गया है। परंतु इन लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बैंकिंग प्रक्रिया में जटिलताएं, दस्तावेजीकरण में जटिलताएं और जमानत संबंधी शर्तों से छोटे उद्यमियों के लिए बाधा बनकर सामने आ रहा है। जिसके परिणामस्वरूप उचित पूंजी के अभाव में वे अपनी व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं।

व्यापार करने के लिए बाजार का अभाव

एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से उत्पादन किए जाने वाले वस्तुओं को राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए बाजारों का अभाव है क्योंकि कई बुनकरों और कारीगरों को डिजिटल बाजार, आकर्षक पैकेजिंग, ई – कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं ब्रांडिंग के बारे में सूचना का अभाव है। जिसके परिणामस्वरूप उन लोगों को अपने उत्पादों का उचित कीमत प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

कच्चे माल की उपलब्धता और कीमतों में वृद्धि

एक जिला एक उत्पाद योजना में हथकरघा बुनकरों, हस्तशिल्पकारों, कारीगरों और अन्य पारंपरिक उद्योगों में उपयोग होने वाले कच्चे मालों के कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है एवं वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। जो बाजार में वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हो रहा है।

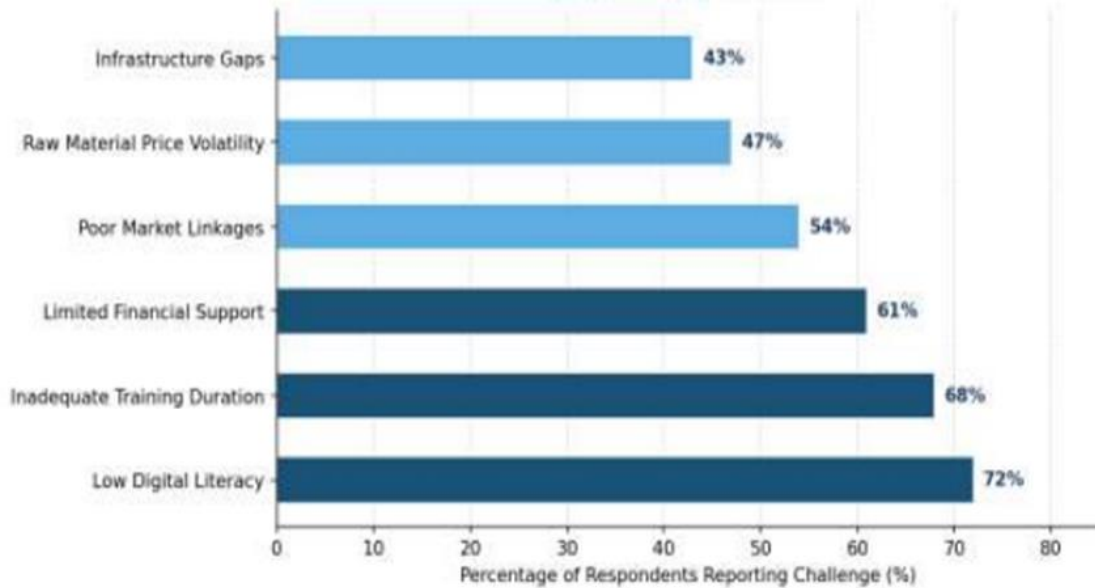
लोगों में डिजिटल साक्षरता का अभाव

वर्तमान समय में ऑनलाइन बाजार और डिजिटल भुगतान व्यवसाय का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कारीगरों, हथकरघा बुनकरों, हस्तशिल्पकारों और अन्य पारंपरिक उद्योगों में काम करने वाले लोगों में साक्षरता स्तर अभी भी काम है। जिसके कारण वे लोग ई – कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं ऑनलाइन व्यापार के अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

आधारभूत संरचना का अभाव

उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम सरकार ने हथकरघा बुनकरों, हस्तशिल्पकारों एवं कारीगरों को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान किया जा रहा है फिर भी कुछ जिलों में जागरूकता का अभाव, प्रशिक्षण का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा का अभाव, सड़क, परिवहन एवं गोदाम जैसी आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण बाजार तक पहुंच, वस्तुओं का उत्पादन और भंडारण की क्षमता प्रभावित हो रहा है।

सूर्य तिवारी और अजीत कुमार झा (2024) तथा डॉक्टर रश्मि अग्रवाल और डॉक्टर जावेद आलम (2023) इनके शोध पत्रों के अध्ययन से पता चलता है की एक जिला एक उत्पाद योजना के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप 43 प्रतिशत, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि 47 प्रतिशत, खराब बाजार नेटवर्क 54 प्रतिशत, सीमित वित्तीय सहायता 61 प्रतिशत, कम डिजिटल साक्षरता 72 प्रतिशत, अपर्याप्त प्रशिक्षण अवधि 68 प्रतिशत का वर्णन अपने क्षेत्रीय सर्वेक्षण में किया है। इस को फिगर में दिखाया गया है –



निष्कर्ष :

इस प्रकार हम कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों, हथकरघा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, हस्तशिल्प और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कारीगरों के संपूर्ण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को पहचान देकर उसके उत्पादन, गुणवत्ता, निर्यात में वृद्धि करना और बाजार उपलब्ध कराना है। इसके साथी इस योजना ने स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना, लोगों में कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण करना तथा आर्थिक सशक्तिकरण का भी प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। इस शोध पत्र में एक जिला एक उत्पाद योजना ने पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने के साथ – साथ आधुनिक तकनीक, नई डिजाइन को विकसित करना, वस्तुओं के गुणवत्ता में सुधार करना, वस्तुओं का पैकेजिंग करना, डिजिटल बाजार पर अपनी वस्तुओं को बेचना और वस्तुओं की ब्रांडिंग के क्षेत्र में कार्य करने वाले कारीगरों की दक्षता में वृद्धि का काम किया है। फिर भी इस योजना में कुछ चुनौतियां जैसे प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीक उन्नयन बाजार उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा, वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चेमाल की उपलब्धता और लागत में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन सामने आ रही है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, विपणन विकास सहायता योजना, प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना, मार्जिन मनी योजना, सामान्य सुविधा केंद्र, उत्तर प्रदेश तकनीकी उन्नयन योजना, उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति (2022) क्रियान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार एक जिला एक उत्पाद योजना स्थानीय स्तर पर लोगों में कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तथा स्थानीय स्तर पर संसाधनों, स्थानीय स्तर पर पारंपरिक कौशल, आत्मनिर्भर भारत, समावेशी आर्थिक विकास एवं आधुनिक विकास के लिए आदर्श मॉडल बन सकता है।



संदर्भ :

1. Singh, S. (2026). One District One Product (ODOP) Scheme: Contributions to Skill Development and Employment Generation in Uttar Pradesh. International Journal of Creative and Open Research in Engineering and Management, 02(04), 1-12.
2. <https://doi.org/10.55041/ijcope.v2i4.827>
3. Patel, Akanksha. (2025). A STUDY ON THE IMPACT OF ODOP SCHEME ON ECONOMY OF UTTAR PRADESH: AN ECONOMIC ANALYSIS. International Journal For Multidisciplinary Research.
4. 7.10.36948/ijfmr.2025.v07i03.45415.
5. Chowdhary, D.A., & Milan, P.R. (2024). One District One Product business model: A review of different countries. Adhyayan: A Journal of Management Sciences, 14(1), 58–61.
6. <https://doi.org/10.21567/adhyayan.v14i1>.
7. Sharma, Anant & Kumar, Pavnesh. (2024). A Study on the Role of the ODOP (One District, One Product) Scheme on Strengthening the Metal Craft Industry in Moradabad Region, Uttar Pradesh. Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation. 19. 119-133.
8. 10.1177/2319510X241239796.
9. <https://www.researchgate.net/publication/381300881>
10. Tewari, S., & Jha, A. K. (2024). Evaluating the performance of ODOP and its role in industrial development of Uttar Pradesh. Journal of Business and Management Research, 16(2), 112–134.
11. <https://isid.org.in/wp-content/uploads/2025/06/WP278.pdf>
12. Agrawal, R., & Alam, J. (2023). Overall impact of the ODOP on economy of the Uttar Pradesh. The Academia, 1(2), 11–17.
13. https://kepgclko.in/WebDoc/PDF/Extra/Vol1Issue2_003.pdf?638760523821598245&%3A~%3Atext=Economy%20of%20Uttar%20Pradesh%20contributes%20to%20the%20financial%20year%202020%2D21
14. Yadav, U.S., & Tripathi, R. (2022). Role of One District One Product (ODOP) of Uttar Pradesh: Strategies and a new initiative for developing global handicraft index. International Journal of Economics and Commerce Research (IJEER), 2(1), 1–15.
15. <https://iaeme.com/Home/issue/IJEER?Volume=2&Issue=1>
16. Tripathi, A. P., & Agrawal, N. (2021). Economic revitalization through ODOP: A case study of Uttar Pradesh. Public Administration and Policy, 24(3), 306–319.
17. Kapoor, Geetika T. (2020). A STUDY OF PERFORMANCE OF ONE DISTRICT-ONE PRODUCT PROGRAMME (ODOP) IN UTTAR PRADESH. Shodh Sarita, 7(28) 216-221.
18. <https://www.researchgate.net/publication/380403365>
19. Invest UP. (2024). ODOP achievement report 2018–2024: Key statistics on employment, exports and skill development. Government of Uttar Pradesh. <https://invest.up.gov.in>
20. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (2020). National Skill Development Mission: Annual report. Government of India.
21. <https://www.upsdm.gov.in/>
22. <https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/One-District-%E2%80%93-One-Product-Scheme-2018.pdf>
23. <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/jan/doc2026123764601.pdf>
24. https://www.indianembassygiers.gov.in/content/odop_product_list-Aug-2025.pdf
25. <https://www.nduat.org/Doc/NAAC/6.2.1%20ODOP.pdf>
26. <https://odopup.in/en/districts>